अध्यक्ष महोदय : बैठिये आप ।

(व्यवधान)

MR. SPEAKER : That is all. Why do you always try to coerce me ?

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : I have not allowed anybody.

Shri Jagpal Singh.....Shri Rajnath Sonkar Shastri.

12.10 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

INCIDENTS OF LOOTING OF PASSENGERS IN CERTAIN TRAINS

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर अपना वक्तव्य दें :—

उत्तर प्रदेश में सियालदाह-जम्मू तवी एक्सप्रैस और गंगा-जमना एक्सप्रैस रेल गाड़ियों में यात्रियों के हाल ही में लूट लिए जाने के समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI P. C. SETHI) : Sir.....

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री महोदय को हिन्दी आती है । हिन्दी में ही जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अगर कहें तो मैं हिन्दी करता जाऊं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कठिनाई हो तो अंग्रेजी में बोलिये और अगर न हो तो हिन्दी में बोलिये ।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई दोनों में नहीं है ।

SHRI P. C. SETHI : Sir, At about 02.15 hrs. on 24-4-1982, when 51 Sealdah-Jammu Tawi Express left Varanasi Station, 10/12 yougnmen boarded a second class 3 tier compartment of the train, which was third from the guard break-van and at the point of knife and pistol started looting the passengers of the compartment. According to the reports received, the Travelling Ticket Examiner of the coach happened to be present in the coach. He objected to the entry of these unauthorised persons, but he was silenced at the point of revolver and was relieved of his watch and cash Rs. 200/-. The miscreants looted passengers of their property worth about Rs. 1,20,000/-. 2 passengers got bullet injuries while 10 others received minor injuries at the hands of the miscreants. When the train reached Jaunpur Station at about 03.30 hrs., the miscreants got down from the train and fled away. The Government Railway Police constables who were escorting the train and the G. R.P. men present at the platform chased the miscreants and even opened fire. As a result of this, the miscreants left behind two brief cases containing Rs. 6147/- in cash, transistor, wrist watch, ornaments and clothes of worth about Rs. 30,000-. The injured persons were given necessary first aid. The Government Railway Police Varanasi has registered a case No. 192 dated 24-4-82 u/s 395/397 IPC and are making investigation. Senior Police Officers are guiding the Police investigation.

As regards the incident in the Ganga-Jamuna Express, it occurred near Unnao Railway Station in Uttar Pradesh. On 23-4-82, at about 23.00 hrs., while 83 Up. Ganga-Jamuna Express was approaching the outer signal of Unnao Station, 3 youngmen entered a 3 tier coach of the train and occupied the seats in front of

**Not Recorded.

the victing, Shri Kashmiri Lal. Subsequently, 4/5 other youngmen also joined them and enquired from him about the contents of the two bags being carried by him. On arrival of the train at Unnao, 4/5 of these youngmen at the point of pistol snatched away 2 bags of silver-slabs and decamped. The other 3 youngmen continued to guard the victim so that he was unable to detrain or raise an alarm. When the youngmen who had snatched the silver-slabs from him had escaped from the station area, the others also fled away. The Government Railway Police, Unnao has registered a case No. 51 dated 24-4-82 u/s 395 IPC. Out of 77 kgs. silver worth about Rs. 1,50,000/- snatched away by the miscreants, 41 kgs. silver slabs worth about Rs. 1,00,000/- has since been recovered by Government Railway Police, Unnao. 3 criminals have also been arrested so far.

The Government Railway Police, who are responsible for safety and security of passengers travelling in trains and their belongings, are making their best efforts to control crime on railways by providing escorts on trains, surveillance over criminals, arresting and prosecuting them in specific cases. Railway Protection Force is assisting the Government Railway Police in this regard. Chief Minister of the concerned States have also been approached by me to ensure that adequate preventive measures are taken in this regard.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : But there is general breakdown of law and order.

12.12 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उत्तर प्रदेश में ला एंड आर्डर बिल्कुल नहीं है । पूर्वी जिलों में डैकोयट्स के गैंग आप्रेट कर रहे हैं । इतनी हालत खराब है । रेलवे क्या करेगी ? उत्तर प्रदेश में कोई ला एंड आर्डर नहीं है ।

In UP they are killing thousands of innocent people, but they are not able to control law and order.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जैसा अभी हमारे वरिष्ठ सांसद ने कहा उत्तर प्रदेश में इस समय ला एंड आर्डर की स्थिति एकदम नहीं रह गई है । यह बिल्कुल सही बात है । इतना ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी ला एण्ड आर्डर की स्थिति नहीं रह गई है । रेलवे में आज सुरक्षा नाम की किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है । जानमाल की कोई गारंटी नही है । निरंतर किराये बढ़ते जा रहे हैं । हिन्दुस्तान के लोग जब एक जगह से दूसरी जगह रेलों से जाते हैं तो यह कहा नहीं जा सकता है कि वे अपने गन्तव्य स्थान पर ढंग से पहुंच पाएंगे या नहीं । आज रेल में ताश, जुआ, शराबखोरी, बलात्कार और अन्य व्यभिचार आये दिन हो रहे हैं जिनकी खबरें समाचार-पत्रों में आये दिन पढ़ने को मिलती हैं । अप्रैल माह में हुई कुछ घटनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । 16 अप्रैल को राजधानी एक्सप्रैस में बम पाया गया । रक्सौल में चलती हुई ट्रेन में 60,000 रु० की डैकेती 14 अप्रैल को हुई । कलकत्ता में एक रेलवे गार्ड था उसको 6 अप्रैल को छुरा भौंक दिया गया । 19 अप गोरखपुर-हावड़ा एक्सप्रैस को 3 अप्रैल को लूटा गया । कलकत्ता में 4 डकैत 3 अप्रैल को रेल डिब्बे में मारे गये, बालीगंज स्टेशन के लोगों ने हमला कर दिया । बाद में पता चला कि वहां कुछ डकैत भी थे । वहां हमारे रेल मंत्री भी गये हुए थे । पटना में असम मेल में 16 अप्रैल

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

को साढ़े चार लाख की डकैती हुई, लूटपाट हुई और 12 यात्री उसमें घायल हुए, और एक नवयुवती की नाक और कान भी काट लिये गये। 428 डाउन दानापुर पैसेंजर को लूटा गया और ढाई लाख रु० की रकम ले गये। भटिंडा, बरौनी में भी घटनायें हुईं। बड़े आश्चर्य की बात है कि माधोपुर लोको शैड से पूरा का पूरा इंजन गायब हो गया। कहां चला गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं। यह एक, डेढ़ महीने की घटनायें हैं।

वाराणसी में रेल डकैती के सम्बन्ध में मंत्री जी ने उत्तर दिया है जिसका एक पैरा मैं पढ़ कर सुना रहा हूं :

24-4-82 को लगभग 02.15 बजे जब 51 अप सियालदाह-जम्मू-तवी एक्सप्रैस वाराणसी स्टेशन से चली, तब 10, 12 नवयुवक इस गाड़ी के दूसरे दर्जे के 3 टीयर डिब्बे में चढ़ गये। यह डिब्बा गार्ड ब्रेकवान से तीसरा था। .....

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has already read those things. Why are you repeating them ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं एग्जाम्पिल दे रहा हूं। इसमें कहा गया है कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने एक टी० टी० के 200 रु० और हाथ घड़ी छीन ली और 1,20,000 रु० मूल्य का सामान लूट लिया। मैं कल उस ट्रेन में यात्रा करते हुए एक यात्री से मिला जो उस डिब्बे में बैठा था, वह हमारे ही क्षेत्र का रहने वाला है और इत्तफाक से वाराणसी हमारा क्षेत्र है जहां यह दुर्घटना हुई जौनपुर के बीच में। उसने मुझे बताया कि लोग चीखते रहे लेकिन बगल में डिब्बे में बैठी हुई पुलिस में से कोई वहां नहीं पहुंचा। और टी० टी० को भी लूटा गया। समझ में नहीं आता कि सरकारी कर्मचारी कैसे काम करेंगे।

चंदौली, वाराणसी में हुई यह एक ही घटना नहीं है। 1949 से लेकर आज तक वहां 98 घटनायें वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में हो चुकी है। हाल ही में 20 दिन के अन्दर 3 घटनायें हुई हैं। चंदौली में 3 मालगाड़ी के डिब्बे लूटे गये। जमालपुर में यात्री गाड़ी में डकैती हुई। हंडिया वाराणसी के पास एक जगह है वहां 25 तारीख को भयंकर लूटपाट हुई और गोली भी चली। एक घटना वाराणसी में और हुई जिससे पता चलता है कि क्या हालत है। पूर्वोत्तर रेलवे में एक स्टेशन है कादीपुर, जो सैदपुर कांस्टीट्यूएंसी में आता है। वहां पर कुछ सशस्त्र लुटेरे डिब्बे में घुस गये और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। गोपाल श्रीवास्तव एडवोकेट नाम के एक लड़के ने एक लुटेरे को पकड़ लिया और उस लुटेरे को लेकर वह आगे के स्टेशन पर उतरा तो वहां स्थानीय पुलिस थी। वह उनको सैदपुर थाने में ले गयी और वहां जाकर उल्टा गोपाल श्रीवास्तव एडवोकेट को पीटा गया जो गाजीपुर में शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी है। उस डकैत को वहां की पुलिस ने छोड़ दिया। इसकी शिकायत बी० आर० एम० से हुई, उच्चाधिकारियों से हुई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। वह डकैत आराम के साथ घूमता रहा। अब वही वहां का स्थानीय डकैत श्री गोपाल श्रीवास्तव को कहता है कि एक बार तुमको छोड़ दिया गया है, अबकी बार नहीं छोड़ा जायेगा।

मैं मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ कि रेलों में दो प्रकार की पुलिस कार्य कर रही

है, एक जी० आर० पी० और दूसरी आर० पी० एफ०। आर० पी० एफ० को अगर देखा जाये तो असल में बात यह है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। क्या आर० पी० एफ० को अधिकार दिलाने के लिये सरकार कोई कानून बना रही है? क्या आर० पी० एफ० को जी० आर० पी० की तुलना में ज्यादा महत्व दिया जायेगा? क्योंकि जी० आर० पी० वहां की स्टेट की लोकल पुलिस होती है जो कि निरन्तर अपराधियों से सांठ-गांठ करती है।

मंत्री महोदय ने रेल बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि ट्रेन डकैतियां और ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत हुई हैं, इस विषय में हम कोई बिल पेश करेंगे, लेकिन आज तक सैकड़ों, हजारों घटनाए हो गई हैं, कोई भी बिल पेश नहीं किया गया है। क्या मन्त्री जी अपने उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई कानून सरकार आर० पी० एफ० को अधिक अधिकार देने के लिये बनायेगी? रेलों में डकैतियां, चोरियां और हत्याएं होती रहती हैं, इनके बारे में स्थानीय ढंग से मुकदमें कायम किये जाते हैं जो कि लम्बे चलते हैं। मुकदमें दर्ज किये जाते हैं, रेल मन्त्रालय का वकील होता है और सरकारी वकील भी होता है, ये दोनों इसकी पैरवी करते हैं। प्रायः देखा यह जाता है कि मुसाफिर कहीं अन्यत्र का है, मुकदमा कहीं अन्यत्र चल रहा है जहां कि घटना होती है। ये सारे वकील एक दूसरे से मिल जाते हैं और मुकदमों की ठीक ढंग से पैरवी नहीं हो पाती।

मैं रेल मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस फाइनेन्शियल इअर के पहले जो दो वर्ष गुजरे हैं, उस पीरियड में कितनी रेल डकैतियों के मुकदमें कायम किये गये और कितने अब तक चल रहे हैं और कितनों का फैसला हो चुका है। जिनका फैसला हो चुका है, उनमें कितने अपराधियों को दंडित किया जा चुका है?

हवाई जहाज की दुर्घटनाए होती हैं, रेलों की भी होती हैं और मुआवजा दिया जाता है। डकैतियों की घटनाएं होती हैं, लूट-खसोट होती है, इसमें लाखों की डकैती पड़ जाती है, जैसा मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया कि गंगा-जमना ट्रेन में जब कि जम्मू-तवी ट्रेन चल रही थी, उसके दो-ढाई घंटे के अन्तर पर उसी स्थान के अगल-बगल में 100, 50 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई। इसको प्रशासन की लापरवाही कहा जाये या अक्षमता कहा जाये? इससे प्रकट होता है कि ट्रेन उसी रूट पर चल रही थी और दो-ढाई घण्टे के अन्तर पर यह घटना हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो मुआवजा दिया जाता है, यह कितना दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है? जितने रुपये की डकैती होती है, क्या पूरा दिया जाता है? कितनी डकैतियों में यह मुआवजे दिये गये हैं?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whatever you may say, you will get reply only with regard to the matters under the Calling Attention Notice. It may help you in some other way, but the reply will be restricted to that.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ऐसा पता चलता है कि यह सब ट्रेन डकैतियां किसी एक खास स्थान पर होती रहती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां ये घटनाएं विशेष तौर से होती हैं, क्या वहां पर कोई विशेष स्क्वैड या पुलिस की व्यवस्था करने के लिए वह तैयार हैं या उनके सामने ऐसी कोई प्लानिंग है।

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

मैं तो यह समझता हूँ कि इन घटनाओं में बहुत ऊंचे अधिकारियों का हाथ है। आज मैं इस हाउस में यह बात निस्संकोच कहूँगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं** कि पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी की एक घटना है। मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। यह बहुत ही अहमियत का सवाल है। मैंने बार-बार इसको इस हाउस में कहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे में वाराणसी सिटी में पांच क्लर्क पंद्रह और बीस साल से काम कर रहे थे। इन पांचों क्लर्कों के बारे में वाराणसी और आस-पास के तमाम लोग जानते हैं कि ये लोग नितान्त बेईमान किस्म के क्लर्क हैं, जो बीस साल से वहां पर हैं। ये क्लर्क घी से भरे हुए ड्रमों में कोलतार मिलाते थे, कीमती पार्सलों में कूड़ा-करकट भरते थे, स्मगलिंग के सामान को सांठ-गांठ कर के व्यापारियों से छुड़वाते थे। कई बार इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। प्रत्येक आदमी इस भ्रष्टाचार को जानता है। अखबारों में भी यह निकला है। अभी हाल में .....

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : We take objection to this. This is not the way to speak.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : **** आप ऐसी बात कह रहे हैं। मैं माननीय सेठी साहब से यह बात कह चुका हूं ****

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he has made some allegations, I will go through the records.

(Interruptions)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठे हुए हैं। वह मेरी बात का जवाब देंगे। मैं उनसे बात कर रहा हूँ।

SHRI RAM SINGH YADAV : Sir, he is making some allegations.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already replied to him.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सीनियर सी टी एस, मि० जयनारायण, वहां पहुँचे। उन्होंने इन चोरों को पकड़ा। जब उन्होंने इन चोरों को पकड़ा, तो इसके बाद पता चला कि इसमें तमाम लोग इनवाल्व्ड हैं। इसमें जो लोग इनवाल्व्ड हुए, वे बहुत ऊंची किस्म के थे। मंत्री महोदय से यह बात माननीय श्री केदार पांडे ने, जो भूतपूर्व रेल मंत्री हैं, भी बताई कि सीनियर सी टी एस ने रेल विभाग की ईमानदारी को बचाने के लिए ऐसा कार्य किया है, बदमाश लोगों को स्थानान्तरित किया है। इतना ही नहीं, श्री धर्मवीर ने, जो श्रम मंत्री हैं और इस समय यहां मौजूद हैं, भी मंत्री महोदय से यह कहा कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। पांच कांग्रेस (आई) के संसद-सदस्यों ने इस बात को माननीय मंत्री जी से कहा। लेकिन मंत्री जी ने इस बात को अनसुना कर दिया। जब मैंने खुद कहा तो मंत्री जी ने यह कहा कि मैं विचार कर रहा हूं, **

मैं पूछना चाहता हूं **

SHRI RAM SINGH YADAV : Sir, these words should be expunged.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already stated that.

Mr. Shastri, please conclude. You have taken so much time.

**** Expunged as ordered by the Chair.

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरा यह प्रश्न है·····

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, I am not permitting you. If you want a reply, you may stop here. I am not permitting you.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not record anything. I have asked the Minister to reply. Please reply to him.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have given him sufficient time.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, I am not permitting you. Without my permission you cannot speak. The Minister may reply.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not ask me. I have already asked the Minister to reply. The Minister will reply.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do not record anything he says. It is without my permission.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you interested in getting a reply? Otherwise, I will call the next speaker.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, I am not permitting him.

SHRI P. C. SETHI : The Hon. Member has raised a lot of points, which are irrelevant.

*(Interruptions)***

**Not recorded

MR. DEPUTY-SPEAKER : Don't record anything he says.

SHRI RAM SINGH YADAV : Sir, he has made some allegations.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down. I will take care of the House. The Minister is replying.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not record.

SHRI P. C. SETHI : He has made some wild allegations, instead of putting questions. He said that**

12.30 hrs.

Shri Rajnath Sonkar Shastri then left the House.

SHRI P. C. SETHI : So far as this incident is concerned, I have given all the details. There is one thing which is pertinent to know in this incident and that is that the Railway Protection Force or GRP were in the fifth coach while this incident took place in the running train in the third coach near the Guard. Therefore, the question of the GRP coming into the third coach while the train was running does not arise.

In respect of these two cases, actually speaking, the GRP and the Railway Protection Force have acted very swiftly and as soon as the alarm was raised, they chased the culprits and that is why a substantial amount of silver as well as some portion of the looted articles from the other train have been recovered.

It is true that the number of dacoities and lootings in the last few years has been on the increase. They were 223 in 1978, 253 in 1979 and 251 in 1980. During 1981 as

* Not recorded.

**Expunged as ordered by the Chair.

[Shri P. C. Sethi]

many as 370 cases of robberies were reported and from January to March, 110 such incidents have happened up to March 1980. But, Sir, within the given authority, the RPF has the authority to protect the railway property. It does not give them any authority and moreover, in respect of this authority, as far as the security of the passengers and the law and order situation is concerned, it is the subject of GRP. It is a dichotomy. Really speaking, it is for consideration and we are going into the subject matter as to how we can best overcome this situation. At present we are only taking action in the sense that I am approaching the Chief Ministers of the States which are concerned, they are mostly West Bengal, U. P., Bihar, Maharashtra and Madhya Pradesh, and I have personally written to them, I am going there, and I have sent the IGP for discussing the problems connected with this problem, to the various State capitals where the incidents are taking place and we are sure that by swift and smart action we will be able to overcome the difficulties to a very great extent.

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल में यह दो लूट-पाट की घटनाओं के सम्बन्ध में जो कालिंग अटेंशन दिया गया है, हो सकता है इसकी विषय-वस्तु बहुत सीमित हो लेकिन जिस बात की ओर हम माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह यह है कि आज जिस तरीके से रेलें कुव्यवस्था का शिकार हो रही हैं, उसको रोकना बहुत जरूरी है । पिछले दिनों इस सन्दर्भ में आपने कई स्टेप्स भी उठाए हैं लेकिन अखबारों के जरिए और क्वैश्चन्स के जरिए हमको ऐसा लगता है कि उसके बावजूद इस सम्बन्ध में कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है । विगत दिनों में कई जगह रेलों में इस प्रकार की घटनायें घटित हुई हैं । जिस तरह की लूट-पाट पहले रेलों में होती थी वही सिलसिला आज भी जारी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले कब ?

श्री हरीश रावत : आपके टाइम में भी काफी घटनायें हुई थीं। उससे तो आज भी स्थिति बेहतर है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आज घटनायें बढ़ गई हैं। क्या बात करते हैं आप ? (**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : रेलों में पैसेंजर्स को जो सेफ्टी मिलनी चाहिए वह अगर नहीं मिलती है तो उसका रेफ्लेक्शन शासन के ऊपर आता है । रेलवे पैसेन्जर्स को पूरे तरीके से सेफ्टी मिले यह देखना सरकार का काम है । आप ने अभी तक क्या मेजर्स उठाये हैं, वे कितने इफैक्टिव हुए हैं तथा ये घटनायें किस तरह से कम हों—इस लाइट में आप को देखना चाहिये । होता यह है कि रेलवे की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति चोरी चली जाती है, रेलवे की जो ट्रेन्स की प्रापर्टी है वह भी चोरी चली जाती है और रेलवे कर्मचारी उस को रोकने की कोशिश नहीं करते । आप की जो फोर्स इन को प्रोटेक्ट करने के लिये है, उस की सहमति के बिना या उस के शामिल हुए बिना, जिस तरह की घटनायें होती हैं, वे घटित नहीं हो सकती हैं । यह बात इस से साबित होती है कि रेलवे में कई जोन्स ऐसे हैं जहां ये घटनायें बहुत मामूली हैं, लेकिन कुछ जोन्स ऐसे हैं जहां ये घटनायें ज्यादा होती हैं और आप का विभाग जानता है कि वे जोन्स कौन-कौन से हैं, वे आइडेन्टिफाइड जोन्स हैं । वहां ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए

कोई कम्प्रीहैन्सिव रेलवे सेफ्टी प्लान आप के द्वारा नहीं बनाया गया है। कहीं पर कोई प्राब्लम आती है तो आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई घटना घटित होती है तो उस व्यक्ति को जो दोषी पाया गया होता है उस को थोड़ा दण्ड देने की कोशिश की जाती है। जब मामला संसद में उठाया जाता है तो आप कुछ कार्यवाही करते है, परन्तु बाद में सब ठप्प हो जाता है। अधिकांश केसेज ऐसे हैं जो डिटैक्ट नहीं हो पाते हैं, चाहे वे चोरी से सम्बन्धित हों या डकैती से सम्बन्धित हों। जब हम मामले को यहां उठाते है तो आप कहते हैं कि इस सीमा तक रेलवे से सम्बन्धित मामला था और उससे आगे दूसरी एजेन्सी से सम्बन्धित मामला है। इस लिये इस में रेलवे कुछ नहीं कर सकती है। आप के इस तरह के जवाब से आम पैसेन्जर्स की कठिनाइयों में कोई कमी नहीं होती है।

आप ने कहा है कि आप राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत कर रहे है। मेरा निवेदन है कि जितने ऐसे ज़ोन्स है वहां के मुख्य मत्रियों तथा वहां की ला-एन्फोर्सिंग एजेन्सीज़ की सम्मिलित बैठक होनी चाहिये और उस में ऐसा कम्प्रीहैन्सिव प्लान तैयार करना चाहिये जिस में चाहे जितना पैसा लगे, लोगों की सेफ्टी की व्यवस्था हो सके। आप 20 करोड रुपया हर साल नुकसान का देते हैं, इस लिये इस का प्लान बनाने में यदि अधिक रुपया भी खर्च हो तो वह करना चाहिये ताकि आप की पब्लिक अण्डरटेकिंग की जो प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिरती जा रही है उस को गिरने से रोका जा सके।

दूसरी बात—इसी सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—हमारे जो ऐसे जोन्स हैं उन ज़ोन्स में जो ट्रेन्स गुज़रती हैं वे प्रायः रात्रि में गुज़रती हैं। यह बात अनेक बार यहां आ चुकी है कि आप ट्रेन टाईमिंग्स को इस तरह से री-शैड्यूल कीजिये ताकि उन ट्रेन्स को रात्रि में न गुजरना पड़े। साथ-ही-साथ इतनी आर्म्ड फोर्स रखिये जो वास्तव में उनकी सुरक्षा कर सकें। आप 4-5 आदमी रखते हैं जो अपर्याप्त हैं। वे अपनी बोगी में सोये पड़े रहते हैं और इस तरफ कोई तवज्जह नहीं देते है कि पैसेन्जर्स की सुरक्षा की उनकी ज़िम्मेदारी है। ट्रेन फूल होती है तो भी कोई पर्वाह नहीं करते। जो टी० टी० लोग होते हैं जिन पर कम्पार्टमेन्ट की ज़िम्मेदारी होती है वे भी सोते हुए जाते हैं। एक तरफ डकैती होती है और दूसरी तरफ वे सोये हुए चले जाते हैं। गार्ड पर सारा मामला छोड़ दिया जाता है तथा गार्ड भी अपनी सुरक्षा के लिये कोई कदम नहीं उठाता है। ये सारी चीजें आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० से सम्बन्धित हैं, क्यों नहीं एक ऐसी यूनीफाइड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बना दी जाय जो सारे मामलों को देखें, जो सेफ्टी से लेकर कहीं भी कोई घटना होती है उनको देखें, उन से सम्बन्धित मुकदमों में क्या होता है, उस को भी देखें। मैं मानता हूं, माननीय सेठी जी स्वयं इन घटनाओं से बहुत चिन्तित हैं और उन्होंने अनेक कदम उठाये भी हैं, परन्तु फिर भी तेज़ी से अनेक कदम उठाने की जरूरत है ताकि रेलवे में आम पैसेन्जर्स को सुरक्षा प्रदान की जा सके और लोगों का आप की इस महान संस्था में जो बिश्वास धीरे-धीरे हट रहा है, उस को फिर से रेस्टोर किया जा सके।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो चिन्ता व्यक्त की है, वास्तव में वह हमारी सब की चिन्ता है।

[श्री प्रकाश चन्द्र सेठी]

यह तुलना करना कि 1978 में कम थे और अब बढ़ गये हैं या उस समय नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। दुर्घटनाएं बराबर हर समय होती रही हैं लेकिन जैसा मैंने अभी बताया है कि पिछले दो-तीन सालों में इन दुर्घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है।

अब जो हमारा संविधान है, उस के मुताबिक, जो रेलवे का ट्रैक है और रेलवे का इलाका है, उस के बारे में छानबीन करने का या मुकदमे रजिस्टर करने का अधिकार गवर्नमैंट रेलवे पुलिस को है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिस की इस समय संख्या लगभग 60 हजार है, उसका काम रेलवे प्रौपर्टी की प्रोटेक्शन करना है। जी०आर० पी० का जो परसोनेल है, उस के बारे में सब रियासतों से पूछा गया था कि रेलवे में जो घटनाएं बढ़ गई हैं, उनके कारण अगर उन की संख्या कम लगती हो, तो उस के बारे में हमें बताएं और इस के लिए जो मांग हमारे पास आई है, वह - उत्तर प्रदेश से करीब 3 हजार की है, 1700 के करीब महाराष्ट्र से है, 300-350 की उड़ीसा से है और इसी प्रकार मध्य प्रदेश से 200-250 की मांग है। इस तरह से कुल मिला कर 6028 के करीब आदमी हम ने और स्वीकृत कर दिये हैं और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए 50 प्रतिशत खर्च रेलवेज को वहन करना पड़ता है और आज ही हम ने इस सम्बन्ध में एक मीटिंग की थी और उस में यह तय किया गया है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए और ऐसे प्रान्तों या इलाकों में जहां ये घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां एस्कोर्ट बढ़ाने के लिए अगर जी०आर०पी० की संख्या और बढ़ाने की बात है, तो उस के बारे में हम सोच सकते हैं और अधिक लोग दे सकते हैं।

अब हमारी आर०पी०एफ० जो है, उस के लिए जो आर०पी०एफ० एक्ट है, उस में उस को रेलवे की प्रोपर्टी की रक्षा करने का अधिकार है लेकिन सैल्फ-डिफेन्स में उन को भी कानूनन हथियारों का उपयोग करने की इजाजत है और वे अपने सेल्फ-डिफेन्स में या किसी नागरिक के डिफेन्स में हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। इस बात को भी कहा गया है कि जब इस प्रकार की घटना हो जाए और उस पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए अगर उस को कोई कार्यवाही इस तरह की करना जरूरी है, तो वह उस को करे। यह आज फैसला किया है और अक्सर वे अपने पास बन्दूक रखते हैं, जिन का कम्पार्टमेंट में उपयोग नहीं किया जा सकता, उस को वहां इस्तेमाल करना संम्भव नहीं होता। इसलिए बन्दूक के अलावा यह जो हमारी आर०पी०एफ० है, जिन को रात में एस्कोर्ट के रूप में सफर करना होता है, उस को पिस्तोल भी दिये जाएंगे। तो जितना इस मामले में संभव हो सकता है, वे सब उपाय हमारी तरफ से किये जा रहे हैं।

कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां पर इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो वहां पर एस्कोर्ट चलती हैं और पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग भी होती है और कई जगहों पर पुलिस बूथ्स भी खुले हुए हैं और यही वजह है कि एलार्म रेज होने पर पुलिस बराबर आती है और ये जो दो घटनाएं हुई हैं, उन में तो वह बराबर आई है और उस ने जो कार्यवाही की है, उस की वजह से माल भी बरामद हुआ है।

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have already noticed this incidence of dacoity

and robbery and in this very House we have repeatedly discussed the matter time and again. In fact, the Hon. Minister of Railways has already admitted that the incidence of dacoity has been on the increase during the last few years. Now the problem is, how to prevent such type of incidents in trains and provide safety to the passengers in our Railways. That is the main problem before us.

One argument is always being advanced in this House. Here also, in the reply, the Hon. Minister states that the Government Railway Police are responsible for safety and security of passengers travelling in the trains. This very point was discussed time and again in this House. Both the Government Railway Police as well as the Railway Protection Force of the Ministry of Railways are responsible for the safe running of trains in our country. So, in this manner saying time and again, that GRP is responsible for the safety and security of the passengers only is not enough while the RPF is only responsible within the Railway premises is not correct interpretation.

I should say that this is not correct because the prime concern of both the State and the Central Government and of all of us is to provide safety and security of the travelling passengers in the train that is the main problem before us.

We all know that the State Government is responsible for law and order maintenance. Similarly, Central Government is responsible for safety and security and also the over-all law and order situation of the country.

So, I would like to ask one clarification from the Hon. Minister. It was the previous practice to provide escort or a party of escort in the trains in areas prone to these dacoities and this sort of disturbances.

May I ask the Hon. Minister whether it would be possible for the Railway Administration to post these security personnel at least in each train or in each bogie so that some sort of security is ensured for the travelling people?

We all know that both the Railway Administration as well as the State Government provide whatever amount of security is required for this purpose.

In this context, I am sure that the whole House as well as all the Hon. Members present here will not grudge posting of adequate sefety personnel in the trains for sefety of the travelling people. The security personnel should be posted in each bogie of a particular train.

Moreover, special security measures should be taken in those areas which are infested with these decoities and robberies and some sort of chaos so that at least people who are travelling in the train will have sort of a feeling of security and confidence that adequate measures have been taken and that there will not be any danger to them.

I think that this compartment was a 3-tier II Class Compartment and specially at night, the lock system is there and generally when T.T.E. is there in the compartment, when somebody knocked at the door, he must have at least asked and he must have seen who are the persons because in those areas this sort of incidents are frequently happening.

When the T.T. or the staff who were present in the compartment were not adequately protected, why have they opened the compartment's door?

Moreover, in his statment, the Hon. Minister has said that decoits were

[Shri Arjun Sethi]

inside the compartment for long, one hour and 15 minutes.

I, therefore, do not know whether it is a fact or not that there must be some sort of connivance so that this could take place inside the train for such a long time, that is, one hour and 15 minutes.

We have discussed in this House and many Hon. Members have suggested that there is no co-ordination between the RPF and also the GRP. I have seen it for myself in my areas in Orissa State specially. I found that there is even ill-feeling between RPF and GRP personnel in particular stations, even though not everywhere. As a result, the Police Department and the RPF and the GRP shift responsibility to one another amongst themselves. In between, these dacoits or miscreants who create disturbance in the train leave scot-free. May I ask the Hon. Minister whether he is in a position, taking into confidence the State Governments which have been affected by this sort of disturbances of the areas which are prone to this type of dacoities and loot, to increase the police personnel, the GRP and the RPF, and provide escort in the trains with adequate number of RPF personnel, whether these measures can be taken, so that people can have security while travelling from one place to another ?

SHRI P. C. SETHI : If any case of connivance of GRP or RPF or any government official or railway official is brought to our notice, I can assure the Hon. House, we will take the severest possible action against such connivance. It is a fact that we have increased the number of GRP personnel and RPF personnel during the course of the last few years. The problem is very ticklish in the sense that, after leaving the railway premises when the miscreants run away into some areas, those areas belong to the State Governments and, therefore, the problem of registering the case, going into investigation, going for search, etc., squarely falls on the State Governments. If the RPF is loaded with the heavy responsibility of registering the case and also going in for investigations, it will create a dual responsibility, with the result that we would not be able to secure the desired results. The best way to secure the desired results is that we should take punitive action and at the same time get a greater coordination effected between the GRP and the RPF. That is what we are doing. As I have pointed out before, the RPF have been asked to open fire ; although passengers are not railway property as such, they have the authority to go to the extent of opening fire in self-defence or in the defence of any person travelling in the train. Therefore, instructions have been issued to them that, whenever they come across any miscreants, they should open fire, and as a result of this type of action which they have taken, about eight or ten miscreants have been killed in the last two or three months. I am sure that, with greater vigilance and better coordination between the RPF and the GRP, we would be able to overcome this menace to a very great extent, as I have said before.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Can it be done without changing the present legal position? Can you order the RPF to fire at miscreants? They can do that only when railway property is to be protected. In fact, the difficulty is because they have no powers....

SHRI P.C. SETHI: I have gone into the Act itself. The Act says that the RPF is there to protect the railway property. But every citizen of India has the authority to open fire in self defence or in the defence of a person who is helpless if he is seeing that crime being committed; even then, the law provides the authority.

PROF. MADHU DANDAVATE : In the past, when they did, they were actually prosecuted. That is the difficulty. In fact, that is the ticklish problem.

SHRI P. C. SETHI : I am thankful to Prof. Madhu Dandavate for reminding me. As I have said, I have gone into the problem; we have got this examined and we find that, for the protection of these persons from the miscreants, they have the authority to do so. However, I would get it examined by competent legal experts and, if necessary, to that extent, get the Railway Protection Force Act amended.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, there is no doubt that the problem of crime on trains affecting the safety of passengers has been enaging the attention of the Government, of this Government, of the previous Government also ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Government only.

SHRI G. M. BANATWALLA : In fact I must say that there are several problems that the trains are facing to-day and the Government is seriously applying its mind to all those problems trying to improve its performance. However, we cannot ignore the public image of the Railways these days and I am constrained to say that the public image is one of recurring accidents, overcrowding, delays, corruption in reservation, repeated thefts, robberies, dacoities and so on. With respect to thefts, dacoities and robberies our record is very distressing. The increasing number of robberies and dacoities have shaken the sense of security of the passengers. Therefore, I would say that still greater attention needs to be paid to this particular problem.

The crux of the whole question is that while trains are the concern of the Central Government, the maintenance of law and order and detection of crimes is the concern of the State Governments. Therefore, the question of dual responsibility is at the base of this whole question. A serious attempt will, therefore, have to be made in order to solve this particular question. Several committees have also gone into this question of safety and security of passengers. In 1976 perhaps there was that Committee, the Kripal Singh Committee and then this Kripal Singh Committee was plainly told by some of the States that they could not provide more security to the passengers than the security that they could provide to their citizens in urban and rural areas. That is the position. There were several other committees earlier to that. I would like to know whether the recommendations of these committees are being properly followed with respect to safety and security of the passengers. What can the Central Government, helpless in the face of the dual responsibility, do ? They hold meeetings with the Chief Ministers. They give directions to State Government. However, one point is borne out very clearly, that despite these innumerable meetings, we have failed to devise a satisfactory system under which the Railway Protection Force, the Government Railway Police and the State Police can all co-operate. I will, therefore, urge upon the Government to consider very seriously this question of removing the dual responsibility. Why should the Central Government itself not take up the question of the protection and security of the passengers in the train. It is very odd that though the Railways are responsible for the safety of goods that they transport, they are not responsible for the lives of the passengers or the luggage that they carry. That is a very odd thing that we have in our railway system.

[Shri G. M. Banatwalla]

Moreover, when a train crosses the borders of two States, the question comes up of relieving the Police guards and substituting them. These are various serious hindrances that come up. It is, therefore, necessary that the Hon. Minister should take up this question with the Chief Ministers and discuss with them the need that this responsibility is also taken up by the Central Government. We may have the deployment of the CRP because of these particular reasons.

13.00 hrs.

We are told about the Railway Protection Force. The point has already come up. Sir, the Government merely relies on the authority of the RPF to open fire for self-defence. I need not go into many of the legal matters with respect to it. This is a very unsatisfactory matter and let us bring in some specific amendments to the RPF Act so that the RPF will act properly and wherever there is any derelection of duty they can also be pulled up very conveniently.

The problem is entrusted to the GRP of the States. We would like to know about the strength of the GRP in the States. Some States have been advised to increase the strength of their GRP.

13.01 hrs.

(SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*] :

Some States have sent their proposal. Others have not sent their proposal. I would like to ask the Railway Minister one specific question : Is he satisfied with the organisation of the Government Railway Police in the different States ? Is it not a fact that the capabilities of the GRP in different States vary ? Is it not a fact that the organisation of the GRP in the different States also differ ? There are some States for example where the Police District is put under a Superintendent of Police. There are however other States where the Railway police do not have an official cadre of its own above the level of the sub-inspector. Therefore, what is being done in order to see that the very organisation of the GRP is strengthened ? There is also the question of financial constraint. We ask the States to increase the number of GRP personnel ; we say that 50% of the expenditure will be borne by the Central Government. But than the States have also made it clear before the Sixth Finance Commission and before the Kripal Singh Committee that their financial constraints do not enable them to increase adequately their GRP personnel. Therefore, this 50 : 50 share of expenditure is not a very happy position and the financial constraints also come in. There is therefore a need for greater central assistance to the States in order to increase not only the strength of the GRP, but also the efficiency of the GRP. There is need for proper training to be given, in the matter of deployment of the GRP, and so on, with respect to thefts, robberies etc. what is being done with respect to this particular aspect ? Sir, the most effective deterrent to a criminal is the physical presence of the armed police. Not only their strength has to be increased, but any financial constraint which may be there, has to be removed. This formula of sharing on 50 : 50 basis by the Central and State Government has got to be revised. Will the Government take that into consideration ? Has any State told you that they are not satisfied with this formula with respect to the sharing of the expenditure ? If so, what has the Government been thinking about it ?

I respectfully submit that large scale dacoities cannot continue without the connivance of the GRP and a certain section of the railway staff itself. Take the incident of Sealdah Jammu-Tawi Express. How easily,

with great ease, has the dacoity been committed? Train came at Varanasi, a group of armed youngsters easily boarded the train. We are told that there was one TTE; he tried to stop their unauthorised entry. The train was at the station, and he tried to stop them, but he was silenced on the point of knife or a pistol. What is happening to the petrolling of the platform at the dead of the night; what is happening to the patrolling of the station and the waiting room? How long were these persons there? Their suspicious movements or anything else did not raise any suspicion in any of the authorities. That dacoity continued in the compartment also for one hour and fifteen minutes, and the decoity was committed with ease. The train then reached the other station, and they got down from the train. Some firing perhaps in the name of selfdefence took place, but dacoits easily evaporated.

All this showns that there have been certain lapses of security. Therefore, will you undertake some enquiry, a proper enquiry in order to ascertain whether there has been any lapse of security arrangements? We are told that there were armed escorts on the train. The armed escorts ought to have been in this very second class three-tier compartment. How far were they? Should they not be deployed at some strategic place? These are the various questions that should be answered.

Further, the Government should also have a proper list of all the vulnerable points and see to it that proper patrolling etc. is being done at these vulnerable points. It is useless telling us that if we bring to their notice any question of connivance of the GRP or the RPF or the staff, then proper action will be taken. I suggest that whenever any major dacoity takes place, the Government *sou motu* should hold a proper enquiry in order to see whether there have been any security lapses or not. The Government is trying its best; we are one with the Government, but these are the various points that are agitating the minds of the people. I hope that the Hon. Minister will try to clarify these points that have been raised.

SHRI P.C. SETHI : Mr. Chairman, Shri Banatwalla has made a lot of suggestions apart from asking a few questions. I can assure him that as far as these two incidents are concerned, in the light of the discussion and the points raised by Shri Banatwalla and Shri Arjun Sethi, I will have a detailed enquiry conducted. And if there is any lapse, what to talk of connivance on the part of the authorities, the persons concerned would be booked.

As far as the question of 50 : 50 sharing is concerned, we have not received any request from the State Governments. Originally, the State Governments were bearing all the expenses of the Government Railway Police, but since quite some time this 50 : 50 formula has been agreed to.

The Hon. Member also wanted to know about the number of Railway Protection Force. It was 20,000 and recently, we have given additional 6000 persons on request of the various State Governments. And if they need more personnel, in the GRP, for a proper execution of the work which is entrusted to them, we are prepared to supplement their force and sanction the required number. Sir, if any request from the State Governments come to have a second look at the 50-50 % formula, we will certainly go into that aspect of the problem, although we have got our own financial constraints.

[Shri P. C. Sethi]

Sir, as far as the question of revision of the Railway Protection Force Act is concerned, in the light of what Shri Dandavate and Shri Vajpayee and many others, including Shri Banatwalla, have suggested, we would get the whole Act scrutinised by a committee of legal experts and to the extent that any change in the Statute of the Railway Protection Force would help the situation, we would certainly consider that.

Beyond this I have nothing more to say.

MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, normally if the amending Bill was seeking to introduce only some marginal changes in the Monopoly and Restrictive Trade Practices Act, I would not have opposed the Bill at the introduction stage. But it is my contention that the very basic structure of the MRTP Act is being distorted and in fact it is a logical consequence of what has been done last week when the Minister for Industry came out with a statement opening out the core sector for big houses as well as FERA companies, of course, under the pretext of stimulating growth and stepping up exports. I feel that the corollary of that particular statement by the Industry Minister is the courage picked up by the Minister for Law, Justice and Company Affairs to come forward with this amending Bill.

Sir, if you look at the very Preamble of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, it states :

> "The Act to provide that the operation of the economic systems does not result in the consentration of economic power to the common detriment for the control of monopolies for the prohibition of monopolistic and restrictive trade practices and for matters connected there with or incidental thereto."

Sir. this is supposed to be the Preamble of the monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969. This very Preamble is being demolished by the amending Bill that has been brought forward or is sought to be brought forward by the Hon. Minister for Law, Justice and Company Affairs.

Instead of bringing forward a Bill to plug the loopholes in the MRTP Act on the basis of the recommendations of the Rajinder Sachar Committee, the amendment is actually seeking to create further loopholes. I have, with me, a copy of the Report of the High-powered expert committee on companies and MRTP Act. Sir, it is a very comprehensive document and this document tries to to put forward constructive and concrete suggestions by which deconcentration of economic power and wealth could be brought out effectively. Instead of picking up those recommendations of the Sachar Committee and trying to plug the loopholes, this amending Bill is trying to create further loopholes.

Sir, I would draw your attention to Section 21 of the MRTP Act on substantial expansion and new undertakings. You will find that Section 21 has already given wide

*Published in Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2 dated 27-4-1982.